

## MAINS MATRIX

### विषय सूची (Table of Content)

1. "माओवादियों के हथियार छोड़ने का समय आ गया है"
2. "सोने से सजी प्रगति की राह"

"माओवादियों के हथियार छोड़ने का समय आ गया है"

(स्रोत: द हिंदू | लेखक: सुमित भट्टाचार्य)

#### 1. प्रसंग (Context)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में माओवादियों से बातचीत की संभावना से इनकार करते हुए उन्हें सरकार की समर्पण और पुनर्वास नीति के तहत मुख्यधारा में लौटने और आत्मसमर्पण करने का आग्रह किया।

सरकार का लक्ष्य 2025 तक माओवाद का समूल उन्मूलन करना है, क्योंकि यह उग्रवादी आंदोलन अब अपने सबसे कमजोर चरण में पहुँच चुका है।

#### 2. पृष्ठभूमि: भारत में माओवादी आंदोलन

- CPI (Maoist) का गठन 2004 में पीपुल्स वार ग्रुप (PWG) और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (MCC) के विलय से हुआ।
- यह आंदोलन किसान संघर्षों और भूमि आंदोलनों में निहित था, और आंध्र

प्रदेश से बिहार तक फैले रेड कॉरिडोर में विस्तारित हुआ।

- अपने चरम पर इस आंदोलन के पास 42 केंद्रीय समिति सदस्य और लगभग 10,000 सक्रिय कैडर थे।

#### 3. वर्तमान स्थिति और पतन

- केंद्रीय समिति अब घटकर केवल 13 वृद्ध और अस्वस्थ सदस्यों तक रह गई है; राजनैतिक ब्यूरो (Politburo) में भी केवल 7-8 सदस्य बचे हैं।
- कैडर शक्ति घटकर 2,000 से भी कम रह गई है, जो माओवादी इतिहास का सबसे निचला स्तर है।
- यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ (बस्तर क्षेत्र) जैसे पारंपरिक गढ़ों में भी माओवादी प्रभाव काफी कमजोर पड़ चुका है।

#### 4. पतन के कारण (Causes of Decline)

##### (a) सुरक्षा उपाय

- बलों का आधुनिकीकरण: कमांडो बटालियन फॉर रिजॉल्यूट एक्शन (CoBRA) और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG) (जिसमें कई आत्मसमर्पित माओवादी शामिल हैं) की तैनाती।
- ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट: करमेट्टा हिल्स में माओवादियों के मुख्यालय और ठिकानों को नष्ट किया गया।
- पिछले 18 महीनों में:
  - 430 से अधिक माओवादी मारे गए,
  - 1,450 ने आत्मसमर्पण किया,
  - और 1,460 गिरफ्तार किए गए।

#### (b) नेतृत्व संकट

- नंबाला केसव राव उर्फ बसवा राजू की मृत्यु ने संगठन में आंतरिक विभाजन उजागर कर दिया।
- नेतृत्व ज्यादातर आंध्र-तेलंगाना के उच्च जातीय वर्गों से रहा, जिससे गोंड जैसे आदिवासी कैडर अलग-थलग पड़ गए।
- तेलंगाना के दलित नेता तिप्पिरी तिरुपति उर्फ देबूजी को नया महासचिव बनाना इस तनाव का प्रतीक है।

#### (c) वैचारिक और सामाजिक आधार का हास

- बौद्धिक समर्थन और शहरी नेटवर्क का क्षरण।
- वैचारिक संघर्ष से सशस्त्रीकरण की ओर झुकाव ने लोकप्रिय वैधता को खत्म कर दिया।
- हिंसा और जबरदस्ती के कारण आदिवासी समुदायों में मोहभंग बढ़ा।

#### (d) शासन और विकास पहलें

- प्रभावित जिलों में बुनियादी ढांचे, कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक पहुँच में सुधार।
- नियामगिरि (ओडिशा) जैसे उदाहरणों में नागरिक समाज की भागीदारी और लोकतांत्रिक आंदोलन ने शांतिपूर्ण विकल्प दिखाए।

#### 5. छत्तीसगढ़ की भूमिका

- आंध्र प्रदेश और बंगाल से निष्कासन के बाद माओवादियों के लिए छत्तीसगढ़ एक सुरक्षित ठिकाना बन गया।
- सलवा जुडूम आंदोलन (2005) शुरू में उल्टा पड़ा — इससे कई आदिवासी माओवादियों की ओर धकेले गए।
- समय के साथ अत्याचारों और लंबे संघर्ष ने आदिवासियों में निराशा और मोहभंग पैदा किया, जिसके

परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर  
आत्मसमर्पण हुए।

## 6. प्रमुख अंतर्दृष्टियाँ (Key Insights)

माओवादी आंदोलन के रणनीतिक पतन के  
मुख्य कारण:

- नेतृत्व का अभाव
- सूचना-आधारित सुरक्षा अभियानों की सफलता
- वैचारिक प्रतिबद्धता में गिरावट
- सामाजिक थकान और आदिवासी मोहभंग

☛ आंदोलन का अत्यधिक सैन्यीकरण, न कि राजनीतिक या सामाजिक लामबंदी, इसके तेजी से पतन का प्रमुख कारण बना।

## 7. आंतरिक सुरक्षा नीति के लिए सबक (Lessons for Internal Security Policy)

- **समग्र दृष्टिकोण:** सुरक्षा अभियानों के साथ-साथ विकास और सुशासन सुधारों की आवश्यकता।
- **पुनर्वास केंद्रित दृष्टि:** उन्मूलन के बजाय आत्मसमर्पण और पुनर्वास को बढ़ावा देना।
- **लोकतांत्रिक विकल्प:** जमीनी आंदोलनों और नागरिक समाज की

पहले दीर्घकालिक शांति के मॉडल प्रस्तुत करती हैं।

- **मूल कारणों का समाधान:** भूमि वंचन, विस्थापन और शासन की कमी जैसे मूल मुद्दों पर ध्यान देना आवश्यक है।

## 8. निष्कर्ष (Conclusion)

भारत में माओवादी आंदोलन अब अपने अंतिम चरण में है — यह आंतरिक क्षरण और राज्य की आधुनिक रणनीतियों के कारण कमजोर हुआ है।

जन-केंद्रित विकास मॉडल और समावेशी शासन व्यवस्था ही पूर्व माओवादी-प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति और एकीकरण सुनिश्चित कर सकते हैं।

## HOW TO USE

प्राथमिक प्रासंगिकता: जीएस पेपर III  
(आंतरिक सुरक्षा)

यह विषय सीधे “विकास और उग्रवाद के प्रसार के बीच संबंध” तथा “आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ” से संबंधित है।

## 1. आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ

कैसे उपयोग करें:

यह लेख भारत की सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में से एक — वामपंथी उग्रवाद

(LWE) — का “पहले और बाद” का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

### गिरावट की व्याख्या:

सिर्फ यह कहने के बजाय कि LWE एक समस्या है, आप इसके पतन के ठोस कारणों का उल्लेख कर सकते हैं:

- **सुरक्षा उपाय:** विशेष बलों जैसे CoBRA और DRG (सर्मपित माओवादियों से बनी) की भूमिका और "ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट" जैसी सफल अभियानों का हवाला दें।
  - आँकड़े (430 मारे गए, 1,450 आत्मसमर्पण, 1,460 गिरफ्तार) सरकार की रणनीति की सफलता के ठोस प्रमाण हैं।
- **नेतृत्व और वैचारिक संकट:**
  - केंद्रीय समिति की संख्या में भारी कमी,
  - प्रमुख नेताओं की मृत्यु,
  - और आदिवासी कैडरों में असंतोष — ये सब आंदोलन के आंतरिक विघटन को दर्शाते हैं।
- **शासन और विकास:**
  - यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है।

- बेहतर बुनियादी ढाँचा, कल्याणकारी योजनाएँ और प्रशासनिक पहुँच ने जनता का विश्वास जीता।
- इसने “मूल कारणों” — जैसे उपेक्षा, विस्थापन और असमानता — को संबोधित किया।

## 2. बाहरी राज्य एवं गैर-राज्य कारकों की भूमिका

### कैसे उपयोग करें:

हालाँकि लेख में इसे स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, लेकिन आंदोलन की संरचना के समग्र कमजोर होने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बाहरी ठिकाने और समर्थन नेटवर्क भी घटे हैं।

### द्वितीयक प्रासंगिकता: जीएस पेपर II (शासन / Governance)

वामपंथी उग्रवाद का समाधान शासन और विकास की गुणवत्ता से गहराई से जुड़ा हुआ है।

### 1. विकास प्रक्रियाएँ और विकास उद्योग (Development Processes and the Development Industry)

**कैसे उपयोग करें:**

लेख का “Governance and Development Initiatives” भाग इस विषय से सीधे जुड़ा है।

आप यह तर्क दे सकते हैं कि LWE का सबसे टिकाऊ समाधान **सैन्य विजय नहीं, बल्कि सुशासन (Good Governance)** है।

- उदाहरण: **नियामगिरी (ओडिशा)** जैसे नागरिक समाज आंदोलनों ने शांतिपूर्ण विकल्प प्रस्तुत किए।
- यह लोकतांत्रिक संघर्ष समाधान का सशक्त उदाहरण है।

## 2. सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप (Government Policies and Interventions)

**कैसे उपयोग करें:**

सरकार की **समर्पण और पुनर्वास नीति (Surrender and Rehabilitation Policy)** एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है।

- बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण करने वालों से इसकी सफलता स्पष्ट होती है।
- यह दर्शाता है कि **दृढ़ सुरक्षा नीति के साथ-साथ करुणामय दृष्टिकोण भी आवश्यक है।**

**सोने से सजी प्रगति की राह**

**1. संदर्भ (Context)**

वैश्विक पूंजी प्रवाह के सिकुड़ने और विदेशी निवेश की अस्थिरता के बीच, भारत को अपने विकास लक्ष्यों के लिए **आंतरिक स्रोतों** पर निर्भर होना पड़ेगा।

लेख में भारत की **वित्तीय आत्मनिर्भरता (Atmanirbharta)** की वकालत की गई है — विशेष रूप से **घरेलू स्वर्ण भंडार (household gold reserves)** को सक्रिय करके।

## 2. मुख्य तर्क और दर्शन (Core Argument and Philosophy)

**आत्मनिर्भरता (Atmanirbharta)** को एक **सभ्यतागत दर्शन** के रूप में प्रस्तुत किया गया है — जहाँ भारत ने ऐतिहासिक रूप से संकटों को अपनी क्षमता में बदला है।

**उदाहरण:**

- हरित क्रांति (Green Revolution)
- स्वदेशी COVID-19 वैक्सीन का विकास

अब भारत को इस दर्शन को **वित्तीय क्षेत्र** में लागू करना चाहिए — बाहरी पूँजी पर निर्भर रहने के बजाय अपने **आंतरिक संसाधनों को सक्रिय** करके।

**नया नारा: “Make in India” से आगे बढ़कर “Fund in India”।**

### 3. स्वर्ण का विरोधाभास (The Gold Paradox)

#### (a) अपार धरेलू स्वामित्व

भारतीय परिवारों के पास लगभग 25,000 टन सोना है, जिसकी कीमत लगभग 2.4 ट्रिलियन डॉलर आँकी गई है — यह भारत के अनुमानित FY26 GDP का लगभग 55% है।

#### (b) भारी आयात निर्भरता

इतना विशाल भंडार होने के बावजूद, भारत अपनी 87% स्वर्ण माँग आयात के माध्यम से पूरी करता है। यह विरोधाभास व्यापार घाटे (Trade Deficit) और चालू खाते के असंतुलन (Current Account Deficit) को बढ़ाता है।

### 4. प्रस्तावित समाधान — पुनर्जीवित स्वर्ण मुद्राकरण योजना (Gold Monetization Scheme - GMS)

लेखक जबरदस्ती या प्रतिबंधात्मक नीतियों को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि भारत में सोना सिर्फ संपत्ति नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक प्रतीक है।

इसलिए, वे विश्व स्तरीय सर्वोत्तम प्रथाओं (Global Best Practices) पर आधारित विश्वसनीय, विश्वास-आधारित स्वर्ण मुद्राकरण ढाँचे का सुझाव देते हैं।

### 5. सफलता के तीन स्तंभ (Three Pillars for Success)

#### (1) अवसंरचना (Infrastructure)

- देशभर में प्रमाणित हॉलमार्किंग और शुद्धता परीक्षण केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करना।
- मानकीकृत मूल्यांकन से जनता का विश्वास बढ़ेगा।

#### (2) लॉजिस्टिक्स (Logistics)

- एक सुरक्षित और पारदर्शी आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) तैयार करना:
  - बैंक वित्तीय लेनदेन संभालें।
  - विशेषीकृत केंद्र सोने का संग्रह, भंडारण और रिडेम्प्शन संभालें।

#### (3) डिजिटलीकरण और विश्वास (Digitalisation & Trust)

- एक डिजिटल “मेटल बैलेंस” प्रणाली लागू करें, जिससे जमाकर्ता अपने स्वर्ण खाते की निगरानी कर सकें।
- विश्वास निर्माण हेतु प्रक्रियात्मक बाधाएँ हटाएँ:
  - जमा पर GST या सीमा शुल्क जांच नहीं।
  - “नो क्वेश्चन आस्क्ड (No Questions Asked)” नीति।
  - पारदर्शी ब्याज/प्रतिफल संरचना।

## 6. आर्थिक लाभ (Economic Benefits)

### (a) सस्ता पूँजी स्रोत (Cheaper Source of Funds)

स्वर्ण-आधारित जमा से 4.5%–6.5% की दर पर फंड जुटाए जा सकते हैं — जो अंतरराष्ट्रीय उधारी लागत से कहीं कम है।

### (b) व्यापक आर्थिक प्रभाव (Macroeconomic Impact)

घरेलू सोने का आंशिक उपयोग भी:

- आयात निर्भरता कम करेगा और चालू खाते में सुधार लाएगा।
- बुनियादी ढाँचा, विनिर्माण और नवाचार के लिए घरेलू पूँजी उपलब्ध कराएगा।
- वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) और औपचारिक वित्तीय प्रणाली पर विश्वास को मजबूत करेगा

## 7. दार्शनिक और रणनीतिक आयाम (Philosophical and Strategic Dimension)

यह पहल केवल आर्थिक नहीं बल्कि सभ्यतागत निर्णय (Civilizational Choice) है — जो निष्क्रिय संपत्ति (Passive Wealth) को उत्पादक पूँजी (Productive Capital) में बदलने का प्रतीक है।

यह दृष्टि दर्शाती है कि — “भारत अपनी प्रगति को स्वयं वित्तपोषित कर सकता है” (Bharat

can fund Bharat)।

भारत को संचयक राष्ट्र (Saver Nation) से निवेशक राष्ट्र (Investor Nation) की ओर ले जाती है।

## 8. निष्कर्ष (Conclusion)

घरेलू सोने का उपयोग केवल आर्थिक सुधार नहीं, बल्कि संप्रभुता (Sovereignty) की दार्शनिक और रणनीतिक घोषणा है।

विश्वास-आधारित वित्तीय ढाँचे और नागरिकों को सशक्त बनाकर, भारत अपनी विकास यात्रा को अपनी शर्तों पर वित्तपोषित कर सकता है।

इस प्रकार, आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं रहेगा — बल्कि एक आर्थिक वास्तविकता बन जाएगा।

## HOW TO USE

मुख्य प्रासंगिकता: जीएस पेपर-III (भारतीय अर्थव्यवस्था)

यह विषय सबसे प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण रूप से “भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संसाधनों की योजना, संकलन, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दों” के अंतर्गत आता है।

### 1. संसाधनों का संकलन (Mobilization of Resources)

कैसे उपयोग करें:

लेख संसाधनों के संकलन की पारंपरिक समस्या का एक ठोस और नवोन्मेषी समाधान प्रस्तुत करता है।

**“स्वर्ण विरोधाभास (Gold Paradox)”**

भारत में घरेलू परिवारों के पास 2.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (GDP का 55%) मूल्य का सोना है, जबकि देश अब भी दुनिया का प्रमुख स्वर्ण आयातक है।

यह आँकड़ा दिखाता है कि भारत के पास विशाल लेकिन अप्रयुक्त राष्ट्रीय संसाधन हैं।

यह उदाहरण घरेलू बचत और निवेश पर आधारित प्रश्नों में प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है।

**वित्तीय समावेशन और गहराई (Financial Inclusion & Deepening):**

यदि स्वर्ण मुद्राकरण योजना (GMS) सफल होती है, तो यह अनौपचारिक एवं गैर-वित्तीय संपत्तियों (जैसे सोना) को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाएगी।

यह वित्तीय गहराई (financial deepening) का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

**संभावित प्रश्न:**

“उच्च घरेलू बचत दर होने के बावजूद भारत उत्पादक निवेश हेतु संसाधनों के प्रभावी संकलन में विफल रहा है। इस संदर्भ में बाधाओं का विश्लेषण कीजिए तथा सुधारात्मक उपाय सुझाए।”

**2. उदारिकरण के प्रभाव (Effects of Liberalization on the Economy)****कैसे उपयोग करें:**

“वित्तीय आत्मनिर्भरता (financial

Atmanirbharta)” का विचार वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के प्रति एक रणनीतिक प्रतिक्रिया है।

**अस्थिरता में कमी (Reducing Vulnerability):**

घरेलू पूँजी (जैसे सोने का संकलन) पर निर्भरता बढ़ाकर और विदेशी अस्थिर पूँजी पर निर्भरता घटाकर भारत अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक झटकों के प्रति अधिक सुदृढ़ बना सकता है।

इससे मुद्रा संकट (currency crises) का जोखिम घटेगा और सामान्य आर्थिक स्थिरता (macroeconomic stability) बढ़ेगी।

**3. सरकारी बजटिंग (Government Budgeting)****कैसे उपयोग करें:**

यह योजना राजकोषीय और मौद्रिक नीति — दोनों पर सीधा प्रभाव डाल सकती है।

**सस्ते सरकारी उधार की संभावना:**

यदि सरकार इन घरेलू स्वर्ण भंडारों के विरुद्ध 4.5%–6.5% ब्याज दर पर उधार ले सके, तो यह बाज़ार से उधार लेने की तुलना में कहीं सस्ता विकल्प होगा, जिससे राजकोषीय घाटा वित्तपोषण की लागत घटेगी।

**चालू खाते का घाटा (Current Account Deficit - CAD):**

घरेलू भंडारों से स्वर्ण माँग पूरी करने पर स्वर्ण आयात में कमी आएगी, जिससे चालू खाते का घाटा सीधे तौर पर सुधरेगा — जो एक महत्वपूर्ण मैक्रोइकॉनॉमिक संकेतक है।



**द्वितीयक प्रासंगिकता: जीएस पेपर-II (शासन / Governance)**

ऐसी योजना की सफलता शासन (governance) और क्रियान्वयन क्षमता (implementation capacity) की वास्तविक परीक्षा है।

**1. विकास हेतु सरकारी नीतियाँ एवं हस्तक्षेप (Government Policies and Interventions for Development)**

**कैसे उपयोग करें:**

“सफलता के तीन स्तंभ” — अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स, और डिजिटलीकरण — मूल रूप से शासन का खाका (governance roadmap) प्रस्तुत करते हैं।

एक प्रभावी स्वर्ण मुद्राकरण ढाँचा तैयार करने के लिए सरकार को —

- हॉलमार्किंग और परीक्षण केंद्रों का राष्ट्रीय नेटवर्क बनाना होगा,
- सुरक्षित और पारदर्शी लॉजिस्टिक प्रणाली स्थापित करनी होगी,
- और विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा।

यह सब दर्शाता है कि राज्य (state) की भूमिका केवल नीति निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्वास निर्माण (trust building) और सक्षम संस्थागत ढाँचा तैयार करने में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

## आज का मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न:

**प्रश्न 1:**

"एक बहुआयामी रणनीति के कारण भारत में वामपंथी उग्रवाद में महत्वपूर्ण गिरावट आई है।" इस रणनीति का विवरण दें और स्थायी शांति के लिए आगे की दिशा पर चर्चा करें। (15 अंक)

**प्रश्न 2:**

"'आत्मनिर्भर भारत' की सफलता 'वित्तीय आत्मनिर्भरता' प्राप्त करने पर निर्भर है।" इस संदर्भ में, राष्ट्रीय विकास के लिए घरेलू पूंजी जुटाने में भारत के सोने के भंडार की संभावनाओं पर चर्चा करें। (15 अंक)